फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 22 प्रभात जयपुर, रविवार 23 अगस्त, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBIT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

epaper.rashtradoot.com

Deccan Queen
The British Luxury Train

"There is nothing as far as I am aware of in any English Railway which can be looked upon as a parallel undertaking"

Hashtag: The Symbol That Changed Social Media

Observed on August 23, International Hashtag Day marks the anniversary of the first use of the hashtag symbol (#) on Twitter in 2007

उत्तर प्रदेश में 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई

इनमें योगी आदित्यनाथ के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव व बसपा चीफ मायावती भी शामिल हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अगस्त। अगले वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश ने अनेक राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। राज्य में 52 नेताओं को करीब 10-10 लाख रुपये की लागत वाली बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई हैं।

- जैकेट की कीमत 10 लाख रूपए है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये सुरक्षा उपाय किए गए हैं।
- पहले चरण में 8 नेताओं को जैकेट्स दी गई हैं। दूसरे चरण में 44 नेताओं को ये जैकेट्स दी जाएंगी। इसके अलावा 98 अन्य नेताओं व प्रमुख व्यक्तियों को अलग-अलग श्रेणियों की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसी बीच राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा ने भी चुनावी तैयारियां शुरु कर दी हैं तथा पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं।
- पार्टी ने जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण कराए हैं। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा विधायक के कामकाज की समीक्षा की जाएगी तथा उम्मीदावरों के नाम भी तय किए जाएंगे।

इन नेताओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती शामिल हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब राजनीतिक दल आगामी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर रहे हैं।

राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था के तहत बुलेटप्रूफ जैकेट दो चरणों में उपलब्ध कराई गई हैं।

पहले चरण में 8 नेताओं को जैकेट दी गईं, जबकि दूसरे चरण में 44 नेताओं को ये जैकेट उपलब्ध कराई गईं। प्रत्येक जैकेट की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये है।

सूची में भाजपा, समाजवादी पार्टी और बसपा सहित, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेता शामिल हैं।

भाजपा के कई अन्य नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। इनमें स्वतंत्र देव सिंह, जयवीर सिंह और महेन्द्र सिंह शामिल हैं।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में 98 नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों को अलग-अलग श्रेणियों की सुरक्षा दिए जाने की भी तैयारी है।

ये ताजा सुरक्षा उपाय 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए राज्य में राजनीतिक गतिबिधियों के अंतिम चरण के शुरू होने से कुछ महीने पहले किए गए हैं।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं और पार्टी ने राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, जबकि जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।

इन नियुक्तियों से संकेत मिलता है कि देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में भाजपा चुनावी रणनीति को मतदान से काफी पहले मजबूत करने पर जोर दे रही है।

भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने सामाजिक और जातीय समीकरणों को मजबूत करने पर भी काम कर रही है।

पार्टी की व्यापक रणनीति के तहत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले नेताओं को संगठन में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न सामाजिक समूहों पर भाजपा का विशेष ध्यान है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में जातीय समीकरण और विभिन्न समुदायों का समर्थन निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

भाजपा ने 2027 के चुनावों से पहले अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सर्वेक्षण भी शुरू कर दिए हैं।

इन सर्वेक्षणों में पार्टी की संगठनात्मक ताकत, संभावित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसीडी ने स्वास्थ्य मिशन के पुराने मामले में पूरक आरोप पत्र पेश किया

जयपुर, 22 अगस्त। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में साल 2016 के टेंडरों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले एसीबी के विशेष न्यायालय में सुनील राठौड़ के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पेश किया है। इस दौरान आरोपी ने अदालत ने सरेंडर कर दिया। मामले में साल 2019 में एसीबी

- वर्ष 2016 के टेंडरों में भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस नीरज के पवन भी आरोपी हैं।

आईएएस नीरज के पवन, लेखाधिकारी जोजी वर्गीस, एएओ दीपा गुप्ता और दलाल अजीत सोनी के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर चुकी है। इसके अलावा, एक अन्य व्यक्ति सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने बताया कि मामला स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए चलाए गए आरोग्य रथ से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि आरोग्य रथ के संचालन को कागजों में दर्शाकर एक करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। एसीबी ने मई, 2016 में अधिकारियों के आवास और कार्यालयों समेत 18 स्थानों पर छापे मारने के बाद एफआईआर दर्ज की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजीब है खेल कूटनीति का

बांग्लादेश के प्र.मंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा की तिथि पहले घोषित हुई, फिर रद्द हो गई और अभी भी उस पर सस्पैंस कायम है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अगस्त। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की इस सप्ताहांत प्रस्तावित भारत यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

- बताया जाता है कि रहमान 23-24 अगस्त को भारत आने वाले थे। पर, अंतिम समय में यह दौरा रद्द हो गया। इसके पीछे कारण शेख हसीना द्वारा नई दिल्ली से ढाका में किए गए वर्चुअल मीडिया संवाद को बताया जा रहा है।
- इसके बाद एक बार फिर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग ने जोर पकड़ा और उस मांग को तारिक रहमान की भारत यात्रा से भी जोड़ा गया।
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रहमान की यात्रा के संबंध में पत्रकारों को बताया, मेरे पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है।
- ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति भवन से पहले एक प्रैस विज्ञप्ति जारी हुई थी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के स्वागत की ड्रैस रिहर्सल के कारण चेंज ऑफ गार्ड सैरमनी नहीं होगी। पर बाद में इस विज्ञप्ति को वापस ले लिया गया था।

शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास इस संबंध में कोई नई जानकारी नहीं है। रहमान की नई दिल्ली यात्रा के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "मेरे पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर मेरे पास कोई जानकारी आती है, तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा।"

इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन ने एक आधिकारिक सूचना वापस ले ली, जिसमें शनिवार को होने वाले 'चेंज ऑफ गार्ड' समारोह को रहमान के पारम्परिक स्वागत की फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण रद्द किए जाने की बात कही गई थी।

राष्ट्रपति भवन की प्रेस विज्ञप्ति से ऐसा संकेत मिला था कि लंबे समय से चर्चा में रही यह यात्रा होने जा रही है। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद यह सूचना वापस ले ली गई।

समारोह को स्थगित करने की घोषणा के बाद राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार दोपहर एक नई सूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि "इस शनिवार चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा" विषय पर शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति वापस ली जाती है।

आमतौर पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हर शनिवार सुबह 30 मिनट का चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है। यदि शनिवार को राजपत्रित अवकाश हो या राष्ट्रपति भवन की ओर से इसकी अलग से अधिसूचना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'डीडीए "आर्ट ऑफ लिविंग" को 5 करोड़ रूपए लौटाए'

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि आर्ट ऑफ लिविंग के सांस्कृतिक कार्यक्रम से यमुना के इको ज़ोन को कोई नुकसान हुआ था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अगस्त। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के नेतृत्व वाले "आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन" को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली डवलपमैंट अथॉरिटी (डीडीए) को आदेश दिया कि संगठन द्वारा जमा किए गए 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लौटाएं। यह जुर्माना 2016 में दिल्ली में यमुना के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बाढ़ क्षेत्र में आयोजित एक विवादित कार्यक्रम को लेकर लगाया गया था।

- आर्ट ऑफ लिविंग ने मार्च 2016 में यमुना किनारे वर्ल्ड कल्चर फैस्टिवल आयोजित किया था। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना इको ज़ोन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया।
- उस समय आर्ट ऑफ लिविंग फाउण्डेशन ने 25 लाख रूपए जमा कर शेष राशि बतौर बैंक गारंटी स्वीकार करने की मांग की थी, पर, बाद में जुर्माने की सारी राशि अदा कर दी, पर, फिर उसने मुकदमा कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि सांस्कृतिक महोत्सव से यमुना के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को नुकसान पहुंचा था। अदालत ने निर्देश दिया कि "आर्ट ऑफ लिविंग" के संरक्षण में संचालित पंजीकृत सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट व्यक्ति विकास केन्द्र द्वारा जमा की गई राशि डीडीए वापस करे।

यह जुर्माना नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने लगाया था। एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को मार्च 2016 में आयोजित "वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल" की तैयारियों के दौरान यमुना के बाढ़ क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। आर्ट ऑफ लिविंग को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बार काउन्सिल ऑफ इंडिया चेयरमैन के कार्यकाल को चुनौती

नई दिल्ली, 22 अगस्त। उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के

- याचिका के अनुसार दो वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है पर मनन कुमार मिश्रा 2012 से चेयरमैन चले आ रहे हैं।

कार्यकाल को चुनौती दी गई है। याचिका वकील योगमाया एमजी ने दायर की है।

याचिका में मनन कुमार मिश्रा के चेयरमैन के रूप में लंबे समय तक बने रहने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि मनन कुमार मिश्रा पहली बार साल 2012 में बीसीआई चेयरमैन बने। मार्च, 2025 में उन्हें फिर निर्विरोध चुना गया था। याचिकाकर्ता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा वंदे मातरम् के सम्मान को राष्ट्रीय मुद्दा बनाए रखेगी

भाजपा ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में वंदे मातरम् पर देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अगस्त। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों वाले पूर्ण संस्करण के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया और इसके इतिहास तथा महत्व को लेकर देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की। यह कदम कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा 1937 के पार्टी फैसले पर कायम रहने और पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के केवल पहले दो अंतरों के गायन की परंपरा जारी रखने के निर्णय के बाद उठाया गया है।

- प्रस्ताव में कांग्रेस कार्य समिति के उस फैसले की कड़ी आलोचना की गई, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस वंदे मातरम् के दो ही अंतरे गाएगी।
- भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा, राजनीतिक सुविधा, तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए वंदे मातरम् के सम्मान के साथ समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- भाजपा महात्मा गांधी के उस बयान को भी प्रचारित करेगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम् साम्राज्यवाद विरोधी नारा है तथा शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से जुड़ा है।

भाजपा ने यहां पार्टी मुख्यालय में नए पदाधिकारियों की बैठक में प्रस्ताव पारित कर वंदे मातरम् के केवल दो अंतरे गाने के कांग्रेस के फैसले की निंदा की। पार्टी ने कहा कि राजनीतिक सुविधा या तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय गीत के सम्मान से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भाजपा ने प्रस्ताव में कहा कि वह वंदे मातरम् की गौरवशाली विरासत को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने बैठक की अध्यक्षता की और बाद में प्रस्ताव को एक्स पर साझा किया।

नबीन ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी ने आज, 22 अगस्त 2026 को वंदे मातरम् के सम्मान और इसकी ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है।"

उन्होंने कहा कि भाजपा 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा 1937 के प्रस्ताव की पुष्टि किये जाने और कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के केवल पहले दो अंतरे गाने के फैसले की कडी निंदा और स्पष्ट रूप से विरोध करती है।

नबीन ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय गीत को "सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण या संकीर्ण वोट-बैंक की राजनीति" के अधीन करने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगी।

उन्होंने कहा, "राजनीतिक सुविधा या तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम् के सम्मान और विरासत से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

नबीन ने कहा कि भाजपा देश के हर कोने में वंदे मातरम् के इतिहास,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी रक्षा गठबंधन में शामिल होने को इच्छुक है बांग्लादेश

ढ ाका, 22 अगस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच बने संयुक्त रक्षा ढ ांचे में शामिल होने की संभावना को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि ढ ाका राष्ट्रीय हितों और बदलती वैश्विक परिस्थितियों को

- प्रधानमंत्री रहमान के सलाहकार ने संकेत दिये।

ध्यान में रखते हुए किसी आर्थिक या रक्षा ढ ांचे में शामिल होने के विकल्प पर विचार कर सकता है।

पाकिस्तान की उर्दू टेलीविजन चैनल दुनिया न्यूज और जीओ न्यूज ने बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से बताया कि ढ ाका अपनी बांग्लादेश फर्स्ट नीति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फूड इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है और उतनी ही तेजी से बढ़ रही है खाद्य असुरक्षा

खाद्य सुरक्षा के तहत खाद्य पदार्थों की स्वच्छता व शुद्धता के व्यापक कायदे कानून तो हैं, पर वे लगातार बढ़ती और जटिल होती फूड इकॉनमी से मेल नहीं खा पा रहे हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अगस्त। महाराष्ट्र फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने रैस्टोरैंट, होटल और बड़ी फूड चेन्स के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उससे एक ऐसी समस्या सामने आई है, जो राज्य तक सीमित नहीं है। भारत में खाद्य सुरक्षा के व्यापक नियम तो हैं, लेकिन देश की तेजी से बढ़ती और लगातार जटिल होती फूड इकॉनमी के साथ इन नियमों के पालन की रफ्तार मेल नहीं खा रही है।

- महाराष्ट्र में नए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आयुक्त तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में खाद्य प्रतिष्ठानों पर हुई कार्यवाही ने जिस सच को उजागर किया है, वह एक राज्य का सच नहीं है, बल्कि पूरे भारत का सच है कि किस तरह से बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है।
- महाराष्ट्र में मैकडॉनल्ड्स सहित कई नामचीन खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच की गई और वहाँ भारी कमियाँ पाई गईं। निरीक्षकों को भारी गंदगी के साथ खाद्य पदार्थों पर कॉकरोच, मक्खियां मिलीं। यह भी पाया गया कि रैफ्रिजरेशन व डीफ्रॉस्ट की भी व्यापक व्यवस्था नहीं है।
- मैकडॉनल्ड्स में, सुधार नोटिस में उल्लिखित 20 कमियों में से 18 कमियां मिलीं।

महाराष्ट्र एफडीए ने निरीक्षण के दौरान गंभीर स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी कमियां पाए जाने के बाद कई प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और दक्षिण मुंबई में मैकडॉनल्ड्स का एक आउटलेट भी शामिल है। इस कार्रवाई में पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर के खाद्य प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।

मई में पदभार संभालने वाले एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढ़े के नेतृत्व में की गई यह कार्रवाई केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें बड़ी संख्या में प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन प्रतिष्ठानों में किस तरह की कमियां पाई गई हैं। निरीक्षकों को कॉकरोच और मक्खियां मिलीं, खाद्य सामग्री जमीन पर रखी हुई मिली, पर्याप्त रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था नहीं थी, खाद्य सामग्री को सही तरीके से डीफ्रॉस्ट नहीं किया जा रहा था, एक खाद्य सामग्री से दूसरी में संक्रमण फैलने का खतरा था, बर्तन गंदे थे और खाना बनाने/परोसने वाले कर्मचारियों की साफ-सफाई में भी कमियां थीं।

कोलाबा स्थित मैकडॉनल्ड्स के एक आउटलेट में निरीक्षकों को पता चला कि पहले जारी किए गए सुधार नोटिस में बताई गई 20 कमियों में से 18 कमियां ऐसी मिलीं, जिन्हें दूर नहीं किया गया था। एक अन्य रेस्तरां में कर्मचारियों को कीड़ों से संक्रमित आटा इस्तेमाल करते हुए पाया गया। अधिकारियों के अनुसार, कर्मचारियों ने बताया कि आटे का इस्तेमाल करने से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अरूण केजरीवाल आरजेएस एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित

जयपुर, 22 अगस्त। राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारियों के संगठन चुनाव में अरुण बेरीवाल अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। उन्होंने 484 मतों में से 356 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। वहीं,

- महासचिव व कोषाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ।

महासचिव पद पर पवन जीनवाल और कोषाध्यक्ष पद पर ज्ञानेन्द्र सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसी तरह, कार्यकारिणी के सदस्य पद पर केदार नाथ, रजनीश, रविन्द्र प्रताप, श्रवण कुमार, स्वाति भगवती, मुकेश सांवरिया व अभिषेक भार्गव निर्विरोध निर्वाचित हुए।